C M Y K

www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 228 नागपुर, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

महाराष्ट्र: चर्चगेट स्टेशन पर बम रखे होने की अफवाह से मची अफरातफरी

मुंबई

मुंबई के सबसे व्यस्त रहने वाले चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर बम की अफवाह ने रेलवे प्रशासन के होश उड़ा दिए, हालांकि ये खबर बाद में अफवाह निकली। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की हेल्पलाइन नंबर पर 10.45 बजे एक अज्ञात कॉल करके स्टेशन पर बम रखे होने की सूचना दी गई थी जिसके बाद स्टेशन पर यात्रियों में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। गौरतलब है कि ये स्टेशन पश्चिम रलवे का मुख्यालय है।

सूचना के बाद आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) दोनों ने तुरंत हरकत में आकर कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि स्टेशन पर तलाशी अभियान के बाद पता चला कि वहां ऐसा कुछ नहीं था लेकिन इस सूचना के बाद यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस आरपीएफ को फोन पर सूचना देनेवाले व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र के जावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में तीन बम धमाकों के छह साल पूरे हो चुके हैं। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 100 घायल हो गए थे।

इरोम शर्मिला शादी के लिए तैयार, हिंदू तरीके से शादी करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र

कोडईकनाल

मणिपुर में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाली इरोम शर्मिला ने अंतत: शादी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने पुराने ब्रिटिश मित्र डेस्मंड कुटीन्हो के साथ शादी करने को लेकर एक प्रार्थना पत्र सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दिया। वह इस समय तमिलनाडु के पहाड़ी शहर कोडईकनाल में रह रही हैं।

शर्मिला ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जबकि सब रजिस्ट्रार ने उनसे कहा कि यह अंतर्धार्मिक विवाह होगा। प्रार्थना पत्र विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। सब रजिस्ट्रार राजेश ने बताया है कि उनका प्रार्थना पत्र नोटिस बोर्ड पर चस्पां कर दिया जाएगा, उस पर 30 दिन तक आपत्ति का इंतजार किया जाएगा। इस अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर शर्मिला और डेस्मंड की शादी करा दी जाएगी। मणिपुर विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद कई महीने पहले शर्मिला अपने मित्र के साथ कोडईकनाल आ गई थीं, तभी से वह यहां हैं। शर्मिला ने कहा, वह शांति की खोज में कोडईकनाल आई हैं और उन्हें यह स्थान पसंद आया है। अपनी असफल लड़ाई की चर्चा करते हुए शर्मिला ने कहा, उन्होंने अपना मकसद नहीं छोड़ा है। शर्मिला ने अफस्पा हटाने की मांग को लेकर 16 साल से ज्यादा समय तक अनशन किया। हालांकि अदालत के आदेश से उनकी नाक से नली डालकर उन्हें तरल खाद्य पदार्थ दिया जाता रहा और अस्पताल में उन्हें कैद करके रखा गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंतत: उन्होंने अगस्त 2016 में अपना अनशन खत्म किया।

शशिकला ले रही हैं स्पेशल ट्रीटमेंट !

घोटालेबाज अब्दुल करीम तेलगी की भी ऐश

बेंगलरु

इन दिनों बेंगलुरु की सेंट्रल जेल सुर्खियों बनी हुई है और इसकी वजह जेल में शुरू एक स्पेशल किचन बताई जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों की अगर मानें तो इन दिनों जेल में अपनी सजा काट रहीं एआइएडीएमके प्रमुख वीके शशिकला तथा करोड़ों रुपए के स्टाम्प पेपर घोटाले के आरोप में जेल में सजा काट रहे अब्दुल करीम तेलगी को इस स्पेशल किचन द्वारा खास ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके खाने के लिए जेल में एक स्पेशल किचन तक बनाया गया है और सूत्र बताते हैं कि इसके लिए अधिकारियों को दो करोड़ रुपए मिले हैं।

वहीं, शशिकला को विशेष सुविधा दिए जाने के मामले में डीजी सत्यनारायण राव (कारावास) ने कहा कि वह सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने रिश्वत की बात को सिरे से नकारते हुए कहा कि हम केवल कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और मैं किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं।

यह खुलासा जेल की वरिष्ठ अधिकारी डी रूपा ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। इसके जरिए उन्होंने अपने

बॉस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। डी रूपा की रिपोर्ट पर अगर सच माना जाए तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में चार साल की जेल की सजा काट रहीं एआइएडीएमके प्रमुख ने स्पेशल किचन बनवाने के लिए जेल अधिकारियों को दो करोड़ रुपयों की रिश्वत दी है। चर्चा यह भी है कि जेल के डीजीपी एचएन राव भी इसमें शामिल हैं। सूत्रों ने काम में हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगाया गया है। बताया जाता है कि डी रूपा ने पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

> *"विश्वसनीय सूत्रों की अगर मानें तो इन दिनों जेल में अपनी सजा काट रहीं एआइएडीएमके प्रमुख वीके शशिकला तथा करोड़ों रुपए के स्टाम्प पेपर घोटाले के आरोप में जेल में सजा काट रहे अब्दुल करीम तेलगी को इस स्पेशल किचन द्वारा खास ट्रीटमेंट मिल रहा है।"*

की है। उन्होंने कहा कि जेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए शशिकला को स्पेशल किचन की सुविधा मुहैया कराई गई है। गौरतलब है कि डी रूपा ने कुछ हफ्ते पहले ही डीआइजी के तौर पर वहां ज्वाइन किया है। उन्होंने गत दिनों परप्पन अग्रहरा सेंट्रल जेल का गहन निरीक्षण किया।

अब्दुल करीम तेलगी की भी है ऐश

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिर्फ शशिकला को नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के स्टाम्प पेपर घोटाले में जेल में बंद अब्दुल करीम तेलगी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। उन्हें तीन-चार सहायक दिए गए हैं, जो उसके पैर-कंधे दबाते देखे गए हैं। वैसे उसे छह महीने पहले एक कोर्ट द्वारा उस वक्त हेल्पर्स दिए जाने का अनुमति दी गई थी, जब वह व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता था।

चीन और कश्मीर मुद्दे पर विपक्ष की पेशबंदी में जुटी सरकार

नई दिल्ली

आगामी मानसून सत्र पर हावी होने वाले कश्मीर और चीन के मुद्दे पर सरकार ने अभी से पेशबंदी शुरू कर दी है। सुरक्षा मामलों की समिति के अहम सदस्य राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज शुक्रवार को विपक्षी दलों को साधेंगे। उन्हें चीन और कश्मीर के बाबत जानकारी भी देंगे और इससे निपटने के लिए सरकारी कोशिशों पर एकजुटता बनने की कोशिश भी करेंगे।

पिछले कुछ महीनों से कश्मीर जहां नासूर की तरह चुभ रहा है वहीं चीन के आक्रामक तेवर ने माहौल गरमा दिया है। यह तय माना जा रहा है कि 17 जुलाई से शुरू होने मानसून सत्र में ये दो बड़े मुद्दे होंगे। ऐसे में 16 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले ही शुक्रवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है। संभव है कि बैठक में सरकार के सहयोगी दलों के नेता भी हों। वहां सुषमा स्वराज चीन के बाबत और राजनाथ कश्मीर के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेंगे। ये दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं और इसीलिए सभी दलों से रायशुमारी की जाएगी।

कश्मीर मे दो दिन पहले ही अमरनाथ यात्रियों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। पिछले दिनों में स्थानीय पुलिस को भी निशाना बनाया गया है। पिछले छह महीने में तकरीबन छह दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि विपक्ष सेना की कुछ कार्रवाइ को लेकर सवाल उठाता रहा है, वहीं सिक्किम के पास डोकलाम में चीन और भारत आमने सामने खड़ा है। हालांकि इसी बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चीन के राजदूत से मुलाकात का विवाद तूल पकड़ गया था, लेकिन विपक्ष पीएम की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा करता रहा है।

बताते हैं कि दोनों मंत्री यह समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत की स्थिति मजबूत है। भूटान उसके साथ है और भारत किसी भी स्थिति में चीन को बढ़त नहीं बनाने देगा। शर्त यह है कि सभी दल सरकार के साथ एकजुट रहें, वहीं कश्मीर के स्थायी समाधान का पूरा फार्मूला बताए बिना यह भरोसा दिया जाएगा कि आतंकी और उन्हें समर्थन देने वाले लोग घिर चुके हैं। बौखलाहट में वह जरूर कुछ घटनाएं कर रहे हैं लेकिन अगले एक दो महीने में स्थिति काबू में होगी।

उपराष्ट्रपति चुनाव: शाह ने संघ से लगवाई मोदी की पसंद पर मुहर, आज उम्मीदवार का एलान

नई दिल्ली

भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद पर संघ की मुहर लगवा ली है। बृहस्पतिवार को झंडेवालान स्थित केशव कुंज में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संघ के वरिष्ठ नेताओं भय्याजी जोशी और कृष्णगोपाल से करीब 45 मिनट तक चर्चा की। माना जा रहा है कि भाजपा आज शनिवार को संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी। यह भी तय है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार की तरह उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी पसंद के जरिए पीएम मोदी एक बार फिर सबको चौंकाएंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए दलित चेहरे पर दांव लगा चुकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण भारत, ब्राह्मण बिरादरी और हिंदुत्व की राजनीति को एक साथ साधेगी। संघ ने वैसे भी ऐसे मामलों में पीएम मोदी को खुली छूट दी है।

तेलंगाना में 300 करोड़ की जमीन का रिकॉर्ड गायब, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

हैदराबाद

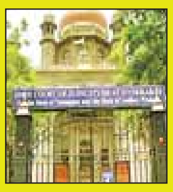

तेलंगाना में 300 करोड़ की जमीन का रिकॉर्ड गायब है। इस मामले में हैदराबाद हाईकोर्ट ने रंगा रेड्डी कलेक्टर को जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर को इस मामले में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश सुनाया है। जस्टिस ए रामलिंगेश्वर ने एच मल्लेश्वर की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए हैं। मल्लेश्वर ने अपनी याचिका में राज्य की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि ये नियुक्त की गई भूमि है, जबकि इसके दस्तावेज गायब हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 अगस्त को होनी है, तो वहीं जज ने इस मामले को लेकर कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

महाराष्ट्र सरकार लांच करेगी उच्च गुणवत्ता के अंगूर, राजस्व में होगी वृद्धि

मुंबई

महाराष्ट्र में अंगूर उत्पादकों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। आने वाले दिनों में अंगूर उत्पादकों के बाजार से बेहतर राजस्व प्राप्त करने की संभावना हैं। राज्य सरकार द्वारा फल की नई किस्मों को लाने का फैसला किया गया है जो रंग, स्वाद और आकार के आधार पर वैश्विक व उच्च गुणवत्ता से मेल खाएगा। राज्य सरकार ने आज महाराष्ट्र अंगूर उत्पादक संघ के साथ मिलकर, नए किस्म के अंगूर आयात करने और उन्हें राज्य में खेती करने का निर्णय लिया। अंगूर उत्पादक संघ के अनुसार, आठ साल बाद फल की नई किस्मों के आयात के संबंध में कोई निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि नए किस्म के अंगूर 2 मिमी लंबे आकार में होगी।

महाराष्ट्र का अंगूर निर्यात सालाना 2 लाख टन के बराबर है। अंगूर उत्पादक इसे नीदरलैंड, जर्मनी और अन्य यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात करते हैं। राज्य के कृषि मंत्री पांडुरंग फंडकर ने बताया, 'बाजार में बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए नए प्रकार के अंगूर की जरूरत थी।

सबसे पहले इन किस्मों का एक वर्ष के लिए परीक्षण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमने नई किस्मों को पेश करने के लिए केंद्र और महाराष्ट्र (सरकार) को अपनी मांग बताई थी। 'महाराष्ट्र अंगूर उत्पादक संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र साहिर ने कहा कि महाराष्ट्र में अंगूर निर्यात का कारोबार, सालाना 15,000 करोड़ रुपये है। 'कुल उत्पादन में, हम केवल 1.5 प्रतिशत अंगूर का निर्यात करते हैं। अगर हमें आधुनिक किस्मों के अंगूर मिलते हैं, तो हम ज्यादा निर्यात कर सकते हैं और अधिक राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। 'उन्होंने कहा कि अंगूर का उपयोग किशमिश बनाने, शराब बनाने समेत कई क्षेत्रों में किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से बाजार को काफी लाभ होगा।

कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने पर पाकिस्तान दे रहा गोलमोल जवाब

नई दिल्ली

पाकिस्तान में फांसी की सजा पा चुके भारत के कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान लगातार सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है। अपने बेटे से एक मुलाकात के लिए लंबे समय से जूझ रही जाधव की मां को पाकिस्तान की तरफ से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने पाकिस्तान की ओर से कूलभूषण जाधव की मां को वीजा दिए जाने की खबर मिलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से जाधव को काउंसलर एक्सेस देने और उनकी मां को वीजा देने के मुद्दे पर कोई बदलाव नहीं आया है, उस पर कोई प्रगति नहीं हो सकी है।

हालांकि पाकिस्तान की मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक कुलभूषण जाधव की मां को पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की ओर से वीजा दिया जा रहा है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले में पाकिस्तान की ओर से किसी तरह की सूचना मिलने से इनकार किया गया है।

गोपाल बागले ने पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के जी-20 बैठक के दौरान मिलने के सवाल पर कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गयी।

उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय की ओर से इसे लेकर एक फोटो जारी की गई थी। बता दें कि चीनी मीडिया की ओर से ऐसी किसी भी मीटिंग से इनकार किया जा रहा है। मोसुल में लापता भारतीयों के सवाल पर गोपाल बागले ने कहा कि हम वहां के अधिकारियों के साथ संपर्क में है।

नारद स्टिंग मामले में ममता बनर्जी के पंचायत मंत्री व सांसद तलब

कोलकाता

नारद स्टिंग मामले में सीबीआइ ने पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी और तृणमूल सांसद काकोली घोष दस्तीदार को तलब किया है।

सीबीआइ ने बुधवार रात सुब्रत मुखर्जी के घर जाकर उन्हें गुरुवार को हाजिर होने का नोटिस दिया। उन्हें निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया था। मुखर्जी ने गुरुवार को हाजिर होने से मना कर दिया। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीबीआइ को 21 जुलाई के बाद हाजिर होने की जानकारी दी।

ज्ञात हो कि नारद न्यूज वेब पोर्टल के सीईओ मैथ्यू सैमुअल ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें पंचायत मंत्री को भी रुपये लेते देखा गया था।

सीबीआइ ने मामले में आरोपी तृणमूल सांसद काकोली घोष दस्तीदार को भी 17 जुलाई को सुबह 11 बजे निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय में बुलाया है। बुधवार रात सीबीआइ के जांच अधिकारियों ने उन्हें पांच बार फोन किया, लेकिन काकोली ने हर बार फोन काट दिया। उन्हें ई-मेल से नोटिस भेजा गया है। ज्ञात हो कि नारद के स्टिंग वीडियो फुटेज में कोकोली को भी रुपये लेते देखा गया था।

कई दिनों से सीबीआइ नारद स्टिंग मामले के अन्य आरोपियों से भी पूछताछ करने में जुटी है जिसमें कोलकाता नगर निगम के उप मेयर इकबाल अहमद व तृणमूल सांसद सुल्तान अहमद, मैथ्यू सैमुअल, आइपीएस एसएमएच मिर्जा व व्यवसायी टाइगर मिर्जा से भी पूछताछ की गई है।

केंद्र चलाएगा जनता के लिए लक्जरी डबलडेकर बसें

नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन में आमूलचूल बदलाव करके वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली डबलडेकर लक्जरी बसें चलाना पर विचार कर रही है। ऐसा करने का मकसद निजी वाहनों के कम इस्तेमाल को प्रेरित करना है। ताकि पर्यावरण प्रदूषण और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक की समस्या से निपटा जा सके।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि वाल्वो की बसें मीथेनॉल से चलेंगी। इसका निर्माण आसानी से देश में ही हो सकता है। सरकार इस बात की योजना बना रही है कि दिल्ली-मुंबई कारीडोर में इलेक्ट्रिक ट्रक और बसों के लिए एक अलग लेन बने।

एसोचैम के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि आगे यह भी योजना है कि डबलडेकर लक्जरी बसों की खेप लाकर दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-लुधियाना को करीब लाया जाये।

इन एसी बसों में अन्य सुविधाओं के साथ ही एयर होस्टेज भी होंगीं। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि इन बसों से यात्रा का खर्च बहुत ही कम होगा। इसका खर्च मौजूदा किराये से भी कम होगा चूंकि यह बसे वैकल्पिक ईंधन से चलेंगी।

यह बसें मीथेनॉल, इथेनॉल या बिजली से चलेंगी। चूंकि मौजूदा सरकार की नीति स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

आज पीएम करेंगे एफडीआइ की समीक्षा

नई दिल्ली

केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में हुए सुधार और उसके असर का आंकलन करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है। बैठक में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि एफडीआइ के प्रवाह को बढ़ाने की दिशा में जिनक रुकावटों को दूर किया गया है उनका कितना असर हुआ है और अभी किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं।

सूत्र बताते हैं कि बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एफडीआइ की नीति में हुए अब तक के बदलावों पर विस्तृत प्रजेंटेशन भी देगा। बैठक में वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री निर्मला सीतारमण के अतिरिक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली और डीआइपीपी सचिव रमेश

अभिषेक भी हिस्सा लेंगे। बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकार एफडीआइ नीति में अगले चरण के सुधार शुरू करने पर विचार कर रही है।

इसके तहत रिटेल और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को और उदार बनाया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए भी नियम आसान बनाये जाने की तैयारी हो रही है।

सूत्र बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में सरकार इस संभावना पर भी विचार कर रही है कि भारतीय कंपनियों को किसी भी परियोजना में अविकसित प्लाटों के लिए भी एफडीआइ लाने की छूट दे दी जाए। हालांकि अभी की नीति में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में सौ फीसद एफडीआइ लाने की छूट है।

इसमें कई शर्तें शामिल हैं। अभी केवल विकसित किये जा चुके प्लाटों जिसमें सड़क, पानी की सप्लाई, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज का काम हो चुका हो, के लिए ही एफडीआइ लाया जा सकता है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में एफडीआइ नीति को उदार बनाने संबंधी कुछ घोषणाएं की थीं। सरकार अब उन पर कदम आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले मौजूदा एफडीआइ नीति की समीक्षा करके यह पता लगाया जाए कि इसका कितना लाभ मिला है।

पिछले साल ही सरकार ने करीब दर्जन भर क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोला था जिनमें रक्षा उत्पादन, सिविल एविएशन, कंस्ट्रक्शन व डवलपमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, रियल एस्टेट और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग शामिल थे।